RAJYA SABHA

Wednesday, The 12th March, 2003/21 *Phalguna*, 1924 (*Saka*)

The House met at eleven of the clock,
MR. CHAIRMAN in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

**301. [The Questioner (Shri K. Rahman Khan) was absent. For answer vide pages 49-50.]*

श्री सभापति : प्रश्न संख्या 302 श्री राजीव शुक्ल।

Return and Rehabilitation of Kashmiri Migrants

*302. SHRI RAJEEV SHUKLA:
DR. ABRAR AHMED:†

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether any Action Plan for the return and rehabilitation of Kashmiri migrants have been prepared; and

(b) if so, the status of the plan?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI HARIN PATHAK): (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) In order to enable safe and honourable return of migrants to their native places in the Valley, the then State Government of J&K had finalized an Action Plan involving a total amount of Rs. 2589.73 crores. The Union Government has agreed to reimburse costs borne by the State Government as per approved norms in the case of those

†The question was actually asked on the floor of the House by Dr. Abrar Ahmed.

Kashmiri migrants who actually return to the Valley. The Action Plan is to be implemented in phases which envisages return and rehabilitation of migrant families in areas where clusters of migrant houses are available and in villages/mohallas in the Kashmir Valley Districts with sizeable Kashmiri Pandit population and where security is already being provided. To begin with, 166 houses forming 15 clusters were identified in Srinagar and Badgam Districts, which are considered safe for the return of the owners of these houses. The list of these clusters was published in the newspapers and steps were taken to identify the families and find their willingness to return to their homes. About 50 families who were registered with the Relief organisation, Jammu were contacted personally to give their consent for return to the Valley on the basis of the package announced by the Government. Interaction meetings with some of these families were also held but as reported by State Government, only two families (not belonging to the particular area) have agreed to return to the valley so far.

The new State Government has indicated that it has identified the shrines in Mattan and Kheer Bhavani where the Kashmiri migrants displaced from these places could be settled temporarily by developing two model clusters containing temporary shelters for Kashmiri migrants, till such time they can repair their existing residential houses. Ministry of Finance has agreed to provide a grant of Rs. 10 crores to the State Government for the reconstruction/renovation of houses and shrines at Kheer Bhavani and Mattan.

श्री राजीव शुक्ल: सभापति जी, सब से बड़ी दिलचस्प बात यह हैं कि दिसम्बर, 2002 से आज तक एक ही जवाब मंत्रालय से मिल रहा है, अगर रिकॉर्ड देखा जाये तो एक ही जवाब मंत्रालय से मिल रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से आप के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ढ़ाई करोड़ से ज्यादा का पैकेज सेंक्शन किया गया था और 7-8 लाख के करोड़ प्रति परिवार देने का प्रावधान था। लेकिन 56 हजार परिवारों में से सिर्फ 2 परिवार इस बात के लिए सहमत हुए हैं कि वे वैली में वापिस जाने के लिए तैयार हैं। इस का कारण क्या है? वे लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे है? वे लोग असुरक्षित महसूस कर रहे है तो क्या सुरक्षा व्यवस्था की कमी है?

श्री हरिन पाठक: सभापति जी, जैसाकि हम सभी को विदित है करीब 10-12 सालों से हम इस समस्या को फेस कर रहे हैं और इस समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार व केन्द्र सरकार हमेशा प्रयत्नशील रही है। मगर जिस तरह से हमारे पड़ौसी देश ने आतंकवादी प्रवृत्तियों को

प्रोक्सी वार के रूप में हमारे सामने रखा है, उस के फलस्वरूप इस समस्या का समाधान करना और विशेषकर जो काश्मीर से प्रवासी आए हुए हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, उन के मन में विश्वास पैदा करना जरूरी हैं क्योंकि घटनाएं बनती रहती हैं। किसी 6 महीने में और किसी सालभर में घटनाएं कम होती हैं और किसी 6 महीने में या सालभर में घटनाएं ज्यादा हो जाती हैं, उसी के फलस्वरूप यह उन के मन में विश्वास सम्पादन करना जरूरी है कि अगर वे अपने घरों में लौटेंगे तो उनकी सेफ्टी, सेक्युरिटी और सलामती का पूरा बंदोबस्त किया जाएगा, उन के ऊपर कोई आतंकवादी हमला नहीं होगा। ये परिस्थितियां बदकिस्मती से नहीं बन पाई हैं, यह जमीनी सच्चाई है।

श्री राजीव शुक्ल: तो इन परिस्थितियों का निर्माण कब तक हो पाएगा क्योंकि अगर आर्मी कैम्प पर हमला होता है तो फिर वे लोग अपने को कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे? उस के साथ-साथ मेरा सैकंड सप्लीमेंटरी यह है कि नेशनल मायनोरिटी कमीशन ने काश्मीरी पंडितों को मायनोरिटीज का दर्जा देने की बात की थी। उस दिशा में क्या प्रगति हुई है?

श्री हरिन पाठक: सभापति जी, माननीय सदस्य के पास जो सूचना है वह अपूर्ण है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन मानने की उन की मांग को स्वीकार नहीं किया है।

डा॰ अबरार अहमद: सभापति महोदय, इस संदर्भ में बहुत बड़ी-बड़ी योजनाएं बनायी हैं और माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में लिखा है कि उन्होंने 166 मकानों और 15 बस्तियों की पहचान भी की, व्यक्तिगत रूप से भी ऐसे 50 परिवारों से बात भी की, लेकिन सिर्फ दो परिवारों के वहां पहुंचाने के बारे में सहमति बन पाई। मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि आतंकवाद के कारण उन में आत्म विश्वास पैदा न कर पाने की जो लाचारी हैं, उन में आत्म-विश्वास बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है? इस के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी डिस्प्लेस्ड पर्संस की हालत जानने के लिए फरवरी 2 को जो सरकार को दिशा-निर्देश दिया है,उस के संबंध में क्या प्रगति हुई है?

उप-प्रधान मंत्री, गृह मंत्रालय तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रभारी श्री लाल कृष्ण आडवाणी: सभापति जी, पिछली सरकार थी या अभी की सरकार है--दोनों सरकारों द्वारा केन्द्र की तरफ से इस बात पर बल दिया गया है कि काश्मीर में नॉर्मलसी आई है या नहीं, इस की एक कसौटी होगी कि वहां पर जो काश्मीरी पंडित शताब्दियों से रहते थे और जो पलायन कर के जम्मू आ गए हैं, दिल्ली आ गए है या देश के अन्य भागों में आ गए हैं, वे वहां पर वापिस स्थापित हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। पिछली सरकार भी - वहां के राज्यपाल भी मुख्य मंत्री भी उन के कैम्प्स में गए थे और उन को पर्सुएड करने की कोशिश की थी। उन्होंने 'हां' की थी, लेकिन वे गए नहीं। अब की सरकार ने इस बात की कोशिश की है और पिछले दिनों में वहां के मुख्य मंत्री, प्रधान मंत्री से भी इस विषय में मिले थे और उन्होंने सुझाव दिया कि हम कोशिश करेंगे कि खीर भवानी और मट्टन जहां पर मकान हैं, जहां पर काश्मीरी पंडितों के कुछ मेले भी लगते

वहां इन को बसाएं। तो प्रधान मंत्री ने कहा कि अच्छा विचार है,आप करिए। उनको कुछ सहायता मांगी तो प्रधान मंत्री ने वित्त मंत्री को कहकर 10 करोड़ की राशि भी उन्होंने स्वीकृत कर दी। अब ये सारे प्रयत्न हैं जिन प्रयत्नों से कोशिश है कि जो ऐसे लोग हैं, जो कैम्पों में रह रहे हैं-कैम्पों में अच्छी स्थिति नहीं है, बुरी स्थिति है, कैम्पों में रहना बहुत भयंकर है और उनको भी सुधारने की कोशिश होती है - उनको पुनर्स्थापित किया जाए, लेकिन जब तक उनके मन में विश्वास पैदा नहीं होता तब तक उनको पुनर्स्थापित करना संभव नहीं है। हमारी तरफ से और प्रदेश की सरकार की तरफ से, किसी की भी सरकार हो, हम इस दिशा में अभी भी लगे हुए हैं और जैसा मैंने आरम्भ में कहा कि एक कसौटी नॉर्मल्सी की यह है।

श्री संजय निरूपम: सभापति महोदय, हर व्यक्ति को उसका गांव अपनी तरफ आकर्षित करता है, इसके बावजूद यदि कश्मीरी पंडित वैली में वापिस नहीं लौट रहे हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह उनकी असुरक्षा है। कितने भी प्रयत्न कर लें, शायद ही वे जाने के लिए तैयार हों। वे आज जम्मू के शरणार्थी शिविरों में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, मुम्बई में रहते हैं। ऐसे में कश्मीरी पंडितों की तरफ से एक सुझाव आया है कि जम्मू-कश्मीर का एक हिस्सा कश्मीरी पंडितों को होम लैंड के तौर पर दिया जाए जिसे वे पनुन कश्मीर का नाम देते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव आया है और यदि ऐसा कोई प्रस्ताव आया तो क्या सरकार इस बारे में सकारात्मक रूप से विचार कर सकती है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: पनुन कश्मीर का सवाल बहुत समय से चला हुआ और उसकी जो कठिनाइयां हैं, वे भी उनको पता हैं। मैं मानता हूं कि अभी के मुख्य मंत्री ने जो प्रस्ताव रखा है वह प्रस्ताव एक प्रकार से एक क्लस्टर डोर या दो टाउनशिप इस प्रकार की डेवलप करना है और अगर यह हो सका तो उससे उस दिशा में शायद हल निकल आए।

DR. KARAN SINGH: Mr. Chairman Sir, the plight of the Kashmiri Pandits, of course, has been one aspect of the continuing tragedy in Jammu and Kashmir, for the last 14 years. It is good that a beginning has been made now, for the first time, to create two complexes in these major shrines. I would like to ask the Hon. Home Minister whether, apart from putting up the cottages and clusters there, any attempt will also be made to provide employment to those people who go back? Because simply living in clusters is not going to be enough. If they go back to the Valley, they must have some positive employment. Is this aspect being addressed?

SHRI L. K. ADVANI: In fact, one reason why people chose to live in very pitiable and pathetic conditions in camps, and not go elsewhere, is that over the years, they are able to get some kind of occupation/

employment there, which they think, they will not get in the new place. But it is certainly true, as the hon. Member has said, when you think in terms of rehabilitating them anywhere, the rehabilitation cannot be confined only to providing them with houses; but it has to be related to some kind of employment too, which in this case also, would be done.

DR. FAROOQ ABDULLAH: Sir, I would like to draw the attention of the Hon. Home Minister to one particular fact. I do not think that the conditions that are prevalent in the Valley are conducive enough for those people to go back. There is a plan being envisaged that they will provide two colonies to them in *Martand* and the other place. But do not think that is going to solve the problem. I have been the Chief Minister of Jammu and Kashmir in the most difficult times, and as you all know already, we ourselves are not safe; we have to have much security around us. Therefore, Sir, any such plan that is made, must be moved very carefully; it is not only a question of employment, but a question of the lives of people residing there. These people will become targets of the *Al Quaeda* and other such movements. Therefore, Sir, any consideration that is done on this must be very carefully sorted out. What I would like to know from the Hon. Home Minister is, whether the present Government that is there, which is really pushing these people to go back, to settle them there, realise the danger to them, as well as the fall-out of that in the nation, if a killing spree starts there?

SHRI L. K. ADVANI: Mr. Chairman, Sir I am sure that no one will push anyone. Afterall, if this proposal has to be implemented, it would be implemented only with the consent of those who are affected. Unless they feel confident, the plan would not be successful. Our earlier efforts were not successful, not because of any lack of will, but because the people there did not feel safe. So they have to be made to feel safe.

Crimes against women

*303. DR. T. SUBBARAMI REDDY:†
SHRIMATI SHABANA AZMI:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether in the year 2002, there had been increasing number of crimes against women;

†The question was actually asked on the floor of the House by Dr. T. Subbarami Reddy.